

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़  
भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

व्यवसायिक परिसर,  
छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड  
कालोनी, कबीर नगर,  
रायपुर (छ.ग.)  
ई-मेल: seiaacg@gmail.com

2985-

क. /एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./ई.सी./कोलवॉशरी/जांज-चांपा/244 रायपुर दिनांक 15/10/2015  
प्रति,

डायरेक्टर

मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन (इण्डिया) लिमिटेड,  
हिन्द हॉउस, साँई परिसर, कामर्शियल काम्प्लेक्स,  
श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर  
जिला - बिलासपुर (छ.ग.) 495 001


- विषय :- मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन (इण्डिया) लिमिटेड, ग्राम-बिरगहनी, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा में कोल वॉशरी क्षमता-0.96 मिलियन टन/वर्ष (थ्रुपुट ऑफ कोल) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में।  
संदर्भ :- आपका का पत्र क्रमांक-निल, दिनांक 12/02/2015 एवं अनुवर्ती पत्राचार दिनांक 08/09/2015

---: 00 :---

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया पत्र दिनांक 12/02/2015 एवं 08/09/2015 का अवलोकन हो।

आपके द्वारा दिनांक 07/12/2010 को खसरा नं. 29/2, 32/3-9, 38/4, 38/5, 38/6 एवं 40/1, कुल भूमि 10.00 एकड़, ग्राम-बिरगहनी, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर चांपा के कोल वॉशरी क्षमता-0.96 मिलियन टन/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत प्रारूप-1 एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित आवेदन प्रस्तुत किया गया था। स्टेट लेवल एक्सपर्ट एप्राईजल कमेटी, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 21/08/2012 को टीओआर जारी किया गया था। लोक सुनवाई दिनांक 28/06/2014 को ग्राम बिरगहनी (ब) कटरा प्राथमिक शाला के पहले शासकीय मैदान, विकासखण्ड-बलौदा, जिला-जांजगीर चांपा में आयोजित की गई थी। लोक सुनवाई दस्तावेज छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 05/08/2014 के द्वारा प्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 18/02/2015 के द्वारा फाईनल ईआईए रिपोर्ट के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रकरण पर एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 158वीं एवं 163वीं बैठक क्रमशः दिनांक 10/07/2015 एवं 26/08/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण श्री पवन कुमार अग्रवाल, डायरेक्टर, मेसर्स हिन्द इनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, जिला-जांजगीर चांपा द्वारा किया गया। उद्योग के सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री वाय.एम. रेड्डी उपस्थित थे। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि परियोजना ग्राम-बिरगहनी, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर चांपा में प्रस्तावित उद्योग है। स्थल का आक्षांश 22°10'51.

  
21244  
आपका पत्र दिनांक 12/02/2015

82°N एवं देशांश 82°30'20.93" E है। निकटतम आबादी ग्राम बिरगहनी 0.7 किमी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन लगभग 2.5 किमी. दक्षिण में है। उद्योग से 10 किमी. के अंतर्गत कोई भी नेशनल पार्क, अभ्यारण और जीवमंडल रिजर्व आदि नहीं है। परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी वन भूमि शामिल नहीं है। बिरगहनी रिजर्व फारेस्ट एवं वित्कूली रिजर्व फारेस्ट 10 किमी. दूरी पर है। उद्योग के राइट बैंक हसदेव केनल 4.7 किमी. पर एवं लीलागर नदी 4.5 किमी. दूरी पर है। स्थल से कोई सतही जल स्रोत (नाला) प्रवाहित नहीं होता है। 25 किमी. की दूरी में मेसर्स क्लीन कोल इंटरप्राइजेस, मेसर्स महावीर कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड एवं मेसर्स के.जे.एस.एल. एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड उद्योग स्थापित है। उद्योग के विभिन्न कार्यों हेतु 495 किली./दिन (घरेलू उपयोग हेतु 05 किली./दिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 490 किली./दिन) जल का उपयोग किया जावेगा। जल की आपूर्ति भू-जल से किया जावेगा। भू-जल के उपयोग हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर ऑथारिटी से अनुमति लिया गया है। कोल वॉशरी वेट प्रोसेस पर आधारित होगी। प्रक्रिया से उत्पन्न औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर एवं सेडिमेंटेशन टैंक की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। उपचार उपरांत औद्योगिक दूषित जल का पुनर्उपयोग किया जावेगा। थिकनर से उत्पन्न कोल स्लज से डीवाटरिंग हेतु बेल्ट प्रेस की स्थापना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल का उपचार सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट द्वारा किया जावेगा। उद्योग परिसर के बाहर औद्योगिक दूषित जल का निस्सारण नहीं करते हुये शून्य निस्सारण की स्थिति रखा जाना प्रस्तावित है। रॉ कोल का इनपुट 9,60,000 टीपीए, वाशड कोल आउटपुट 76,8000 टीपीए तथा वॉशरी रिजेक्ट/मिडलिंग्स 1,92,000 टीपीए होगा। कोल वॉशरी से उत्पन्न रिजेक्ट कोल के उपयोग हेतु मेसर्स क्रस्ट स्टील एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा 0.06 मिलियन टन/वर्ष, मेसर्स जी.आर.स्पंज एण्ड पावर लिमिटेड द्वारा 0.66 मिलियन टन/वर्ष एवं मेसर्स महेन्द्रा स्पंज एण्ड पावर लिमिटेड द्वारा 0.066 मिलियन टन/वर्ष के लिये अनुबंध किया गया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोल क्रशर में बैग फिल्टर स्थापित किया जायेगा तथा सभी कन्व्हेयर सिस्टम को ढंकना प्रस्तावित है। डस्ट सप्रेसन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जावेगा। जल एवं वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए परिसर में अच्छी हाउस कीपिंग अपनाया जायेगा। श्रमिकों को धूल मुखौटा (डस्ट मास्क) दिया जायेगा। वाहन से उत्सर्जित धूप के नियंत्रण हेतु वाहनों का नियमित रूप से रख रखाव भी किया जायेगा। रॉ कोल एसईसीएल की माईस यथा छाल / कुसमुण्डा / दीपका गोवरा क्षेत्र से सड़का मार्ग से ढंके हुये वाहनों के द्वारा वॉशरी तक लाया जाना प्रस्तावित है। कोल का परिहवन सड़क मार्ग से किया जायेगा। जल, वायु आदि गुणवत्ता अध्ययन दिसम्बर 2012 से फरवरी 2013 के मध्य किया गया है। अध्ययन में हवा बहाव की दिशा मुख्यतः उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर है। 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 02 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमुने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है। मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.<sub>2.5</sub> 15.1 से 27.1 माईकोग्राम / घनमीटर, पी.एम.<sub>10</sub> 25.1 से 45.3 माईकोग्राम / घनमीटर, एसओ<sub>2</sub> 6.1 से 14.5 माईकोग्राम / घनमीटर तथा एनओ<sub>x</sub> 6.9 से 18.2 माईकोग्राम / घनमीटर पाई गई है। परिवेशीय वायु गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार उपचार उपरांत पीने योग्य है। परिवेशीय ध्वनि स्तर 40.65 डीबीए से 47.89 डीबीए पाया गया। मिट्टी में किसी प्रकार का संदूषण (कंटामिनेशन) इंगित नहीं होता है। कोल वॉशरी से परिवेशीय वायु में पी.एम.<sub>10</sub> की अधिकतम वृद्धि 1.6 माईकोग्राम / घनमीटर, एसओ<sub>2</sub> की अधिकतम वृद्धि 0.9 माईकोग्राम / घनमीटर एवं एनओ<sub>x</sub> की अधिकतम वृद्धि 5.5 माईकोग्राम / घनमीटर होगी। उद्योग की कुल भूमि 10.00 एकड़ है, जिसमें वॉशरी एरिया— 2.50 एकड़, स्टोरेज एरिया—2.45 एकड़, इंटरनल रोड हेतु 1.75 एकड़ एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 3.30 एकड़ भूमि पर किया जायेगा। आंतरिक मार्गों को पक्का

किया जावेगा। गारलेण्ड ड्रेन बनाया जावेगा। रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना किया जायेगा। 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका प्लांट परिसर के चारों तरफ विकसित किया जावेगा। सी.एस. आर. के अंतर्गत विभिन्न कार्य में किया जाना प्रस्तावित है।

जन सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव / विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

1. गुडमहन क्षेत्र के सभी गांव में मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराया जावे।
2. प्रस्तावित कोल वॉशरी द्वारा पर्यावरण के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हुये स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर दिये जावे। उद्योग क्षेत्र में वृक्षारोपण संबंधी कार्य कराया जावे।
3. सड़कें खराब होने के कारण बरसात के समय भारी कीचड़ होने से दुर्घटनायें होने की आशंका है। गर्मी के समय भारी वाहनों के आवाजाही से धूल उड़ती है। अतः मुख्य सड़क मार्ग का डामरीकरण किया जावे तथा सड़कों के किनारे सघन वृक्षारोपण किया जावे।
4. सिंचाई से वंचित गांवों में सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था की जावे। आसपास के गांवों में बोरिंग करवाकर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जावे।
5. उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोला जावे। विकास कार्यों में प्रबंधन की ओर से व्यय करने हेतु राशि निर्धारित की जावे। ✓
6. कोल वॉशरी के वाहनों के आवागमन से दुर्घटनाओं की आशंका रहेगी।
7. कोयले के धूल से फसलों को क्षति पहुंचेगी। पेड़ पौधों में धूल जमा होकर धान के फसलों तथा कृषकों को भारी नुकसान पहुंचेगा।
8. सामुदायिक भवन, शमशान घाट, तालाबों में पचरी निर्माण, प्राथमिक शालाओं में शौचालय, सायकल रखने के लिये शेड की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जावे। ✓
9. भू-जल में कमी होना स्वाभाविक है। अतः भूजल संरक्षण हेतु उपाय किये जावे।

उद्योग द्वारा बताया गया कि मूलभूत सुविधा हेतु सामाजिक विकास दायित्व कोष के तहत पेयजल एवं अन्य सुविधा आसपास के क्षेत्र में प्रदाय की जावेगी। सड़क मार्गों पर जल छिड़काव, कोल कशिंग क्षेत्र में आटोमाइजर द्वारा जल छिड़काव तथा तथा बैग फिल्टर लगाया जावेगा। आवागमन के लिये उपयोगी मार्ग पी.डब्ल्यू.डी. का है। अतः यथोचित अनुमोदन के बाद सड़कों का मरम्मत किया जावेगा। प्रतिमाह गांव में स्वास्थ्य संबंधी कैंप लगाया जावेगा। पेयजल की समस्या के निवारण हेतु कोष से नलकूप तथा बोरिंग किया जावेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना सामाजिक दायित्व कोष से की जावेगी। आसपास के क्षेत्रों का विकास कार्यों में खर्च किया जावेगा। यातायात के दौरान दुर्घटना के रोकथाम हेतु समुचित प्रयास किये जायेंगे। स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जावेगा। भू-जल के उपयोग हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति लिया गया है।

समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का स्थानीय स्तर पर निरंतर मॉनिटरिंग किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई। इस हेतु सभी स्टेक होल्डर्स यथा ग्राम पंचायत, ग्रामीण, उद्योग के कर्मचारी, परिवहनकर्ता तथा प्रबंधन के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुये उद्योग प्रबंधन द्वारा एक कमिटी बनाई जावे। यह कमिटी उद्योग को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों, उद्योग द्वारा अपनाये गये पर्यावरण संरक्षण हेतु अपनाये गये उपायों तथा उद्योग द्वारा किये गये सामाजिक - आर्थिक विकास कार्यक्रम आदि की मॉनिटरिंग करेगी। कमिटी द्वारा सुझाये गये कार्यों को प्रबंधन द्वारा तत्परता से संपादित किया जावेगा। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सहमति व्यक्त की गई। समिति द्वारा सर्वसम्मति से इस बाबत पर्यावरणीय स्वीकृति में शर्त अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

विचार विमर्श उपरांत समिति द्वारा सर्वसम्मति से मेसर्स हिन्द इनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-बिरगहनी, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर चांपा के कोल वॉशरी क्षमता-0.96 मिलियन टन/वर्ष (थ्रुपुट ऑफ कोल) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 50वीं बैठक दिनांक 23/09/2015 में चर्चा की गई। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ग्राम-बिरगहनी, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर चांपा के कोल वॉशरी क्षमता-0.96 मिलियन टन/वर्ष (थ्रुपुट ऑफ कोल) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार ग्राम-बिरगहनी, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर चांपा में कोल वॉशरी क्षमता-0.96 मिलियन टन/वर्ष (थ्रुपुट ऑफ कोल) को पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- 1) Land requirement shall be 10.0 acres (washery - 2.5 acres, storage area - 2.45 acres, internal roads- 1.75 acres and green belt area - 3.30 acres).
- 2) Project proponent shall ensure that annual throughput capacity of the coal washery shall not exceed 0.96 million tonnes / annum.
- 3) No water bodies (including natural drainage system) in the area shall be disturbed due to activities associated with the setting up / operation of the washery.
- 4) Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial and domestic effluent. Thickner followed by sedimentation ponds of adequate capacity shall be provided for treatment of industrial effluent. Domestic effluent shall be treated in septic tank and soak pits. Project proponent shall provide effluent treatment plant before commissioning of the plant. Treated / un-treated effluent collection pond shall be lined suitably to prevent seepage in to ground for avoiding ground water contamination. All the effluent treatment system shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay otherwise similar alternate arrangement shall be made. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment & Forests, Government of India or Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur (whichever is stringent).
- 5) Any liquid effluent what so ever generated from industrial activities shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within premises. All the industrial effluent generated shall be re-circulated / reused after proper treatment. The un-treated / treated domestic effluent shall not be discharge into the river or any surface water bodies. The treated domestic effluent shall be used for plantation purpose after proper disinfection. Project proponent shall make proper arrangements of suitable drains / pipe networks to ensure adequate flow for utilization of treated effluent inside the premises. The concept of zero discharge shall be maintained all the time except during monsoon. Arrangements shall be made that effluents and storm water do not get mixed.
- 6) Project proponent shall provide adequate measuring arrangements for the measurement of water utilized in different categories and effluent generated before commissioning of the plant.
- 7) Water consumption shall not exceed 495 cum / day (industrial use - 490 cum / day and domestic - 5.0 cum / day). Water will be sourced from ground water as per approval of Central Ground Water Authority. Water requirement

shall be optimized. Wet process based on closed water cycle system shall be adopted. Minimum water drawl for makeup purposes shall be ensured.

- 8) Project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements such as bag filters at all point and non point sources for the control of emissions from processes / operations and for the control of emissions during the handling & transportation of raw coal / rejects etc. before commissioning of the plant and maintained in proper order during operation. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. The particulate emissions from any point source shall not exceed  $50 \text{ mg} / \text{Nm}^3$  under any circumstances.
- 9) In case of transportation of raw coal / rejects by road, the project proponent shall maintain fugitive dust emissions to the minimum level in the areas of road transportation routs to ensure compliance National Ambient Air Quality Standards prescribed including black topping / asphaltting / concreting and maintenance with requisite water sprinkling arrangements. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Vehicles used for transporting the mineral shall be covered with tarpaulins and optimally loaded. The project authority shall obtain permission from competent authority of State Government for use of roads for transportation of raw coal, washed coal, reject / fines etc. through roads. The project authority shall ensure transportation of washed coal and middling / reject through railway as maximum as possible.
- 10) All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the industry, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency.
- 11) Adequate number of permanent ambient air quality monitoring stations (not less than four) in the core zone as well as buffer zone for  $\text{PM}_{2.5}$ ,  $\text{PM}_{10}$ ,  $\text{NO}_x$  and  $\text{SO}_2$  shall be set-up in the down wind direction as well as where maximum ground level concentrations are anticipated in consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board. Monitoring net-work shall be designed taking into account the environmentally and ecologically sensitive targets, land use pattern, location of the stacks, meteorological conditions and topographic features including existing ambient air quality data. The data so collected shall be properly analyzed and submitted to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilapur, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India, Bhopal in every six months.
- 12) Project proponent shall install separate electric metering arrangements with time totalizer and interlocking arrangement for the running of pollution control devices. These arrangements shall be made in such a fashion that any non-functioning of pollution control device / devices shall immediately stop the electric supply to the raw coal supply system and shall remain tripped till the pollution control device / devices are made functional again / rectified to achieve the desired efficiency.
- 13) The raw coal, washed coal and coal wastes (rejects) shall be stacked properly at earmarked site (s) within stockyards fitted with wind brakers / shields. Adequate measures shall be taken to ensure that the stored minerals do not catch fire.

- 14) Project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Project proponent shall obtain authorization from Board for management and handling of hazardous materials as per Hazardous Wastes (Management, Handling and Trans boundary Movement) Rules, 2008 (if required).
- 15) All the internal roads shall be made pucca before commissioning of the plant. The project proponent shall adopt good housekeeping practices. The roads shall be regularly cleaned. Avenue plantation shall be developed along the roads. Facilities for parking of vehicles / trucks carrying coal, waste rejects shall be created within the unit premises. No public place shall be used for parking of vehicles / trucks.
- 16) Project proponent shall take proper action to control the noise pollution. Project proponent shall install appropriate noise barriers / control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation to control the noise. Earplugs / ear muffs etc. shall be provided to the employee working in the high noise areas. The noise level shall not exceed the limits 75 dB (A) during the day-time and 70 dB (A) during the night-time within the factory premises. Project proponent shall take adequate measures for control of noise level below 85 dB (A) in the work environment. Workers engaged in noisy areas shall be periodically examined to maintain audiometric record and for treatment for any hearing loss including rotating them to non-noisy / less noisy areas.
- 17) Project proponent shall provide appropriate arrangements to avoid air pollution, water pollution, noise pollution etc. during construction phase and during transportation of plants / machineries / equipments / construction materials etc. to the propose site. For controlling fugitive dust during transportation and construction works, regular sprinkling of water in village roads and other vulnerable areas of the plant shall also be ensured. The emission from vehicles engaged for transportation of plants / machineries / equipments / construction materials etc. to the site shall be ensured within prescribed vehicle emission norms. First aid and sanitation arrangements shall be made for the drivers and other contract workers during construction phase.
- 18) The construction of effluent treatment plant and installation of air pollution control equipments shall be taken up simultaneously with other civil / mechanical works at the propose site. The progress of the activities related to the project shall be submitted periodically to Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India, Bhopal.
- 19) Project proponent shall provide adequate number of influent and effluent quality monitoring stations / points in consultation with Chhattisgarh Environment Conservation Board. Regular monitoring shall be carried out for relevant parameters. Regular monitoring of surface and ground water quality including heavy metals (Hg, Cr, As, Pb) shall be undertaken and the project area to ascertain the change in the water quality, if any, due to leaching of contaminants from disposal area / project area. Result and data collected shall be analyzed to ascertain the status of water quality and findings shall be submitted. Continuous monitoring of ground water level and quality shall be carried out by establishing a network of existing wells and constructing new piezometers at suitable locations at the proponent's cost in and around project area in consultation with Regional Director, CGWB, Central Region, Bhopal.

- 20) Adequate safety measures shall be provided in the plant area to check / minimize spontaneous fires in raw coal yard, rejects yard etc. especially during summer season. Copy of these measures with full details along with location plant layout shall be submitted to Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India, Bhopal.
- 21) At least 3.30 acres (about one third of the total plant area) shall be used for green belt development. Width of green belt shall not be less than 15 meter all along the boundary of the plant premises. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Industry shall ensure that at-least three years old plants shall be planted for green belt development. Project proponent shall abide by the decisions taken by Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India / Central Government/ Central Pollution Control Board from time to time in this regard. Tree density of 1500-2000 trees per hectare with local broad leaf species should be maintained.
- 22) Project proponent shall provide garland drains with appropriate check dams all along the raw coal, dust, washery rejects dump / storage areas etc. to avoid any possibility of erosion (wearing away) during rain. Garland drain (size, gradient & length) and sump capacity shall be designed keeping 50% safety margin over and above the peak sudden rainfall and maximum discharge in the area adjoining the project site. Sump capacity shall also provide adequate retention period to allow proper settling of silt material. Sedimentation pits shall be constructed at the corners of the garland drains. Project proponent shall provide adequate collection and treatment arrangement for proper management of storm water. The surface run-off shall be de-silted through a series of check dams and drains. The storm water shall be collected in storage tanks and used for industrial purpose, so as to reduce the ground water consumption.
- 23) The project proponent shall also comply with all the environment protection measures and safeguards recommended in the EIA/EMP report. Further, the company must undertake socio-economic development activities in the surrounding village like community development programme, educational programmes drinking water supply and health care etc.
- 24) Project proponent shall adopt the code of practice for coal washeries issued by Central Pollution Control Board.
- 25) Project proponent shall adopt rainwater-harvesting technique in the project area and residential area (if any) for recharge of ground water. The rainwater-harvesting technique shall be incorporated right from the design stage of all structures. Project proponent shall develop rainwater-harvesting structures to harvest the rainwater for utilization in the lean season as well as to recharge the ground water table. A detailed scheme for rainwater harvesting to recharge the ground water aquifer shall be prepared in consultation with Central Ground Water Authority / State Ground Water Board. A copy of the same shall be submitted within three months to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India, Bhopal.
- 26) Project proponent shall establish an environmental management cell to carryout function relating to environmental management under the supervision of senior executive who would directly report to the head of

organization. A full-fledged laboratory with qualified technical / scientific staffs to monitor the influent, effluent, ground water, surface water, soil, stack emission and ambient air quality etc. shall be provided.

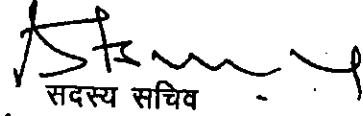
- 27) To ensure the generation of employment in the local areas, recruitment shall be done by inviting applications first from the local residents of the Chhattisgarh State. In case of non-availability of suitable candidates for certain post in the first attempt, the project proponent may call the applications as second call not only from local residents of the Chhattisgarh State but also from other State.
- 28) Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking; mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crutch etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- 29) Occupational Health Surveillance of the all workers shall be done on a regular basis i.e. at-least once in a year and records maintained as per the factories act.
- 30) Project proponent shall also ensure the availability of adequate pastureland for cattle feed after acquisition of land. Project proponent shall also facilitate the respective Gram Panchayats for development of alternative pastureland for cattle feed in the villages as per demand of concerning Gram Panchayat(s).
- 31) Adequate funds shall be allocated for undertaking CSR activities (apart from committed plantation) and in any case it shall not be less than 02% of the profit. Project authority must undertake socio-economic development activities in the surrounding villages like community development programmes, educational programmes, drinking water supply and health care etc. Details of activities shall also be submitted to Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India, Bhopal. The funds earmarked for the environment protection measures shall not be diverted for other purpose and year-wise expenditure should be reported to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India, Bhopal. Local laboures shall be given employment during construction and subsequently absorbed in the plant.
- 32) SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to revoke the clearance if conditions stipulated are not implemented to the satisfaction. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to amend / cancel any of the conditions and add new conditions and make further stringent the emission / effluent limit as and when deemed necessary in the interest of environmental protection, change in the project profile or non-satisfactory implementation of the stipulated conditions etc.
- 33) The project proponent shall advertise in at least two local newspapers widely circulated in the region around the project, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned within seven days from the date of this clearance letter, informing that the project has been accorded environmental clearance and copies of clearance letter are available with the Chhattisgarh Environment Conservation Board and may also seen at Website of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change,



Government of India at [www.envfor.nic.in](http://www.envfor.nic.in) and website of SEIAA, Chhattisgarh at [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org).

- 34) A copy of the clearance letter shall be sent by the proponent to concerned Panchayat, Zila Parisad / Municipal Corporation, urban local Body and the Local NGO, if any, from whom suggestions / representations, if any, received while processing the proposal. The clearance letter shall also be put on the website of the Company by the proponent.
- 35) Half yearly report on the status of implementation of the stipulated conditions and environment safeguards shall be submitted to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India, Bhopal.
- 36) Regional Office of the Ministry of Environment and Forests at Bhopal will monitor the implementation of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report and Environment Management Plan along with the additional information submitted from time to time shall be forwarded to the Regional Office for their use during monitoring. Project proponent will up-load the compliance status in their website and up-date the same from time to time at least six monthly basis.
- 37) The project authority shall constitute a monitoring committee comprising of representatives of all stake holders i.e. Gram Panchayat, villagers, workers, transporters and management etc. This committee shall monitor the conditions stipulated in the environmental clearance, environmental protection measures adopted, socio-economic development activities / community development programmes undertaken etc. The committee shall monitor the above matters at-least once in a month; during which, factual situation regarding above matters will be discussed. The proceedings of the committee shall be recorded in writing along with suggestions (if any). Project management shall take immediate action on the basis of observations / suggestions of the committee. A copy of the proceedings of the committee shall be submitted to Regional Officer, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur for information.
- 38) The project authorities shall inform the Regional Office as well as the SEIAA, Chhattisgarh regarding the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities and the dates of start of land development work and commissioning of plant.
- 39) Full cooperation shall be extended to the Scientists / Officers from the SEIAA, Chhattisgarh, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India /Regional Office, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India, Bhopal / the CPCB / the Chhattisgarh Environment Conservation Board, who would be monitoring the compliance of environment status.
- 40) In case of any deviation or alteration in the proposed project from those submitted to this SEIAA, Chhattisgarh for clearance, a fresh reference should be made to the SEIAA, Chhattisgarh to assess the adequacy of the condition(s) imposed and to add additional environment protection measures required, if any. No further expansion or modifications in the plant should be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India / SEIAA, Chhattisgarh.
- 41) Concealing factual data or submission of false / fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal

- of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- 42) The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.
  - 43) The above stipulations would be enforced among others under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and rules there under, Hazardous Materials (Management, Handling and Trans Boundary Movement) Rules, 2008 (as amended up to date) and its amendments, the Public Liability Insurance Act, 1991 and its amendments. The proponent shall ensure to provide for the costs incurred for taking up remedial measures in case of soil contamination, contamination of groundwater and surface water, and occupational and other diseases due to the washery operations.
  - 44) The issuance of this environmental clearance does not convey any property rights in either real or personal property, or any exclusive privileges, nor does not authorize any injury to private property or any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or Local laws or regulations.
  - 45) Any appeal against this environmental clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.



सदस्य सचिव

राज्य स्तर पर्यावरण, समाघात निर्धारण प्राधिकरण,  
छत्तीसगढ़

पु. क. / एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. / कोलवॉशरी / जांज-चांपा / 244 रायपुर दिनांक / / 2015  
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492001
2. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, सीबीडी-कम-ऑफिस काम्प्लेक्स, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली - 100 032
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यवसायिक परिसर, छ.ग. हॉउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कबीर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)
4. डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विंग, द्वितीय मंजिल, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 100003
5. मुख्य वन संरक्षक, (सी) क्षेत्रीय कार्यालय (वेस्ट जोन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड क्रमांक - 3, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (मध्यप्रदेश)

सदस्य सचिव

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,  
छत्तीसगढ़